आदर्श हिमाचल

खबरें विकास की, मुद्दे जनता के

Aadarshhimachal.com | aadarshhimachal@gmail.com

शिमला 13 फरवरी से 19 फरवरी, 2023 | RNI No. HPHIN/2017/70267 | ◆ वर्ष 8 ◆ अंक 08

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में किया हिमाचल निकेतन का शिलान्यास

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेशवासियों को हिमाचल निकेतन के रूप में ठहरने का मिलेगा तीसरा विकल्प

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में 57.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पांच मंजिला हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण से दिल्ली जाने वाले हिमाचल के विद्यार्थियों और अन्य लोगों को ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध होगी।

इस भवन में दो वीआईपी कमरेए विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 36 तथा 40 सामान्य कमरों की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त स्टॉफ के लिए तीन कमरों की सराय डोरमैट्रिज की सुविधा होगी। इस भवन के बेसमेंट में 53 वाहनों और 87 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस भवन में कुल 81 कमरे होंगे।

इस अवसर पर हिमाचल वासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के अतिरिक्त अब इस भवन के निर्माण से दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हिमाचली विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी। हिमाचल निकेतन विद्यार्थियों को पढ़ने तथा रहने की आरामदायक सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एम्स में चिकित्सा सुविधा के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली जाने वाले प्रदेशवासियों को हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन में रहने की सुविधा उपलब्ध होती है। हिमाचल निकेतन से अब राष्ट्रीय राजधानी में हिमाचलियों को रहने का तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचलवासी प्रतिवर्ष विशेष तौर से सर्दियों में पर्यटन की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों की ओर रुख करते हैं। नई दिल्ली में ठहराव के दौरान उनको भी हिमाचल निकेतन में रहने का एक अन्य विकल्प उपलब्ध होगा।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के साथ वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल में लोक निर्माण विभाग के मंत्री निर्माणाधीन भवन की समीक्षा भी करेंगे, ताकि भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर सम्मानित किया और परियोजना का विवरण देते हुए भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया।

इस अवसर पर नई दिल्ली में रह रहे हिमाचलियों के विभिन्न संघों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। इनमें हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशनए केजीबीसी संस्थान, अखिल भारतीय हिमाचल संयुक्त मोर्चा और शौर्य हिमाचल शामिल थे। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, आरएस बाली, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी व सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक केवल सिंह पठानियाए मुख्यमंत्री के ओएसडी कुलदीप सिंह बांशटू, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा तथा आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का किया आग्रह

बीबीएमबी को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के भी दिए निर्देश

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें राज्य की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की जलविद्युत क्षमता के लगभग 12000 मेगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जल विद्युत विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व सृजन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में सौर ऊर्जा दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्यमियों को निवेश हितैषी तंत्र प्रदान किया जाएगा ताकि वे अविलंब अपनी परियोजनाएं स्थापित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उपायुक्तों को अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक अनुमतियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा परियोजनाओं से विभिन्न स्तरों पर समझौता करने पर विचार कर रही है। पहले स्तर पर ऋण अदायगी की अवधि तक के लिए और दूसरा स्तर जलविद्युत परियोजना के हिस्से पर ऋण अदायगी की समाप्ति के बाद का होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ सतलुज जल विद्युत निगम एसजेवीएन द्वारा कार्यान्वित की जा रही लुहरी विद्युत परियोजना का मामला भी उठाया और परियोजना की व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड बीबीएमबी द्वारा हिस्सेदारी एवं बकाया भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शानन परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और इसे आगे के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने लेह की तर्ज पर राज्य के स्पिति क्षेत्र में हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई.चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ई.चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार भूमि एवं बिजली उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्रीले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऊर्जा सरप्लस राज्य है और प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य ऊर्जा परियोजना को राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को सम्मानित किया और उन्हें हिमाचल प्रदेश आने के लिए आमंत्रित भी किया। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और संजय अवस्थीए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ाए आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

शिमला में नाबार्ड ने आयोजित किया स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023.24

शिमला। नाबार्ड द्वारा शिमला मे वर्ष 2023- 24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया । इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप मे मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भाग लिया। सेमिनार मे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई। सेमिनार मे प्रदेश मे जिला स्तर पर बैंकों के सीडी रेशों को सुधारने पर भी बल दिया है । इसके अलावा नाबार्ड व बैंकों द्वारा लोन देने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने को लेकर मंथन किया गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने बताया कि प्रदेश की 8 जिलों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशों 40 फीसदी से कम है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सीडी रेशो का पैमाना 60 प्रतिशत तय किया गया है। इसलिए आने वाले समय में इसको बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। लोन टर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नाबार्ड की ओर से महिला शशक्तिकरण ए ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि पर विशेष रुप से फोकस क्या गया है। वही स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए नाबार्ड विभिन्न तरीकों से मंच प्रदान कर रहा है।

विश्व बैंक की एक टीम ने किया राज्य का दौरा

हिमाचल की दिशा में हरित विकास पहलों को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। विश्व बैंक की एक टीम ने दक्षिण.एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सतत् विकास जॉन रूमे की अध्यक्षता में 5 व 6 फरवरी 2023 को राज्य का दौरा किया। इसी कड़ी में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में रेजीलिएंट पर्वतीय समुदायों में नए कार्यक्रमों की संभावनाओं पर एक बैठक आयोजित की गई। विश्व बैंक की टीम को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार हरित विकास से जलवायु अनुकूल हरित हिमाचल की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। पर्यावरणए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डीईएसटी का उद्देश्य सतत् समावेशी हरित रेजीलिएंट हिमाचल की दिशा में हरित विकास पहलों को प्रोत्साहित करना है।

बैठक के दौरान राज्य में जिन नई परियोजनाओं में प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता की आवश्यकता है उनपर भी चर्चा की गई। इन योजनाओं में राज्य में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए ग्रीन.ईवी.मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए समर्थन शामिल है। ग्रीन इंडिया मिशन एप्रोच के तहत हिमाचल के लिए हाइड्रो सस्टेनेबिलिटीए सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और नेचुरल कैपिटल मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल कैचमेंट और पर्यावरण प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए सभी 12 जिला और क्षेत्रीय परियोजनाओं में शहरों में आवागमन सुचारू बनाना शामिल है।

बैठक के दौरान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शहरी और ग्रामीण के सुरक्षित एवं सुचारू प्रबंध के माध्यम से राष्ट्रीय स्रोत प्रबंधन ;एनआरएमद्ध के समर्थन के लिए भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त एमएसडब्ल्यू डंपिंग साइट विकसित करने राज्य में प्लास्टिक निष्पादन के लिए एमआरएफ स्थापित करनेए खतरनाक कचरे के लिए सामान्य टीएसडीएफ और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करनेए मीथेन सीएच के प्रभाव तथा भूजल प्रदूषण आदि को कम करने पर भी चर्चा की गई। औद्योगिक अपशिष्ट के सुरक्षित निष्पादन के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में माइक्रो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना के माध्यम से कुशल जल प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल पुनर्भरण के निपटान और पुन: उपयोग के अलावा शासन एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर भी गहन चर्चा की गई।

मुख्य सचिवए प्रबोध सक्सेना ने कहा कि एक इकाई के रूप में नदी बेसिन दृष्टिकोण के साथ विकासात्मक योजनाओं और रणनीतियों के सामंजस्य के लिए और भू.उपयोग योजनाए स्थानिक योजना पर काम करने, वन जलग्रहणए जल सुरक्षाए आपदा प्रबंधन और कृषि विकास योजनाओं को लैंडस्केप दृष्टिकोण में विकसित करने और तथा एकीकृत परिदृश्य पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ाया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक जॉन रूमे ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।

विश्व बैंक टीम के साथ समन्वय कर रहे निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ललित जैन ने बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश में हरित विकास के लिए विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। विश्व बैंक की टीम में प्रैक्टिस मैनेजर.जल, सुमिला गुल्यानीए कार्यक्रम प्रमुख सतत विकास नतालिया कुलिचेंको, वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ पीयूष डोगरा, प्रमुख आपदा जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ दीपक सिंहए प्रमुख संचालन अधिकारी आइपेक अलकन, वरिष्ठ कृषि व्यवसाय विशेषज्ञ आदर्श कुमार, टीम प्रमुख कारमेन यी बतिस्ता और मैथ्यूज मुलक्कल व रामानुजम शामिल थे।

सरकार से मिली मदद और कौशल के संगम से महिलाओं ने संवारी तकदीर

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

मंडी। सरकार से मिली मदद और अपने कौशल के संगम से मंडी जिला की डलाह पंचायत की महिलाएं उद्यमिता की ऐसी सफल गाथाएं लिख रहीं हैंए जो दूसरों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण भी बनी हैं। हरा सोना कहे जाने वाले बांस से विभिन्न उत्पाद तैयार कर महिलाओं ने अपने जीवन में आर्थिक हरियाली का नया मार्ग खोजा है। वहीं सेपू बड़ी, टेडी बीयर, स्वेटर जुराबें अगरबती इत्यादि तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर अपनी तकदीर को ही नहीं संवारा है, बल्कि अपने घर का सहारा भी बनी हैं। जिला मण्डी के विकास खंड द्रंग की ग्राम पंचायत डलाह की महिलाएं आज स्वाबलंबन की मिसाल बनी हैं। कोठी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक खेती से हटकर अब बांस से उत्पाद तैयार कर रही हैं, महिलाओं का यह समूह बांस के उत्पाद बनाकर उन्हें बेचकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहा है। ये महिलाएं बांस की टोकरियां, किल्टे एसूप सहित बांस के उत्पाद बनाकर तीन से चार लाख रूपये तक आमदनी अर्जित कर रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बाहरी राज्यों में आयोजित मेलों में भी विक्रय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।

इन महिलाओं को मुख्यमंत्री ग्राम कौशल विकास योजना के तहत बांस उत्पाद बनाने का तीन महीने की ट्रेनिंग भी विभाग द्वारा दी गए है। ट्रेनिंग के दौरान इन महिलाओं को तीन हजार रुपए का भत्ता भी प्रतिमाह दिया गया। जिला मण्डी के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हिम ईरा नाम से मार्केट यार्ड खोला गया है जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। बांस के उत्पादों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं आमला, आम, नींबू, लिंगड के अचार के साथ सेपू बड़ी, अरबी डंठल बड़ी, माह बड़ी, अमचूर, ढींगरी मशरूम, हल्दी, खजूर व बांस के उत्पाद, कॉटन कुशन, टैडी बीयर, स्वैटर, जुराबें व ऊन के उत्पादों भी तैयार कर रहीं है। साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए गई अगरबत्ती, दीए, धूपबत्ती, मूर्तियों के साथ ही कई तरह के उत्पादों भी तैयार कर रहे हैं। लक्की कोठी स्वयं सहायता समूह की प्रधान कुसमा देवी का कहना है कि बांस के उत्पाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद तथा प्रशिक्षण दिया गया इसके साथ ही विपणन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी लेकिन अब बांस के उत्पाद तथा सेपू बड़ी, स्वेटर, अगरबतीए टेडी बीयर इत्यादि निर्मित कर अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं।

लकी कोठी समूह की सचिव अंजली कुमारी का कहना है कि उनके उत्पादों की डिमांड काफी रहती है मंडी शिवरात्रि तथा अन्य जगहों पर आयोजित मेलों में भी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की डिमांड काफी रहती है जबकि बांस से तैयार उत्पादों को अन्य राज्यों के मेलों में भी विक्रय किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई उनके हुनर की तारीफ करता है तो सुकूं मिलता है इसके साथ साथ ही आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भाव भी निर्मित होता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को स्टार्ट अप के लिए 2500 रुपए तथा रिवाल्विंग फंड के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 25000 रू की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रत्येक समूह को 50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला मण्डी के 14 ब्लॉक में कुल 7878 स्वयं सहायता समूहों में 60301 महिलाएं पंजीकृत हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार इन समूहों पर इस वर्ष मंडी जिला में 28 करोड़ खर्च कर रही है। ये सभी समूह बैंक से लिंक किए गए हैं।

कुल्लू में एक दिन में अधिकतम चार उड़ानें ही भर सकेगा पैराग्लाइडर पायलट

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

कुल्लू। पैराग्लाइडिंग में लापरवाही के चलते होने वाली हादसों को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। अब एक ग्लाइडर पायलट दिन में अधिकतम चार उड़ानें ही भर सकेगा। इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग साइट पर सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में उपायुक्त ने पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को निर्देश जारी कर दिए हैं।

बुधवार को पैराग्लाइडिंग एवं रिवर राफ्टिंग की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने की। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग साइट का हर 15 दिनों में समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। नए पायलटों को लाइसेंस के लिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का अनुशंसा-पत्र आवश्यक रहेगा। पायलट के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक परीक्षा भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पायलट के अनुभव एवं प्रोफेशनलिज्म को जांचा जा सके।

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी पैराग्लाइडिंग संचालकों सहित पायलट के मेडिकल टेस्ट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। वहीं निगरानी कमेटी विभिन्न साइटों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करें तथा नई पैराग्लाइडिंग साइटों को सुरक्षा की दृष्टि से उचित होना भी सुनिश्चित करें।

विभिन्न पैराग्लाइडिंग गतिविधियों से जुड़े हुए पायलटों को कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित किए जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से पैराग्लाइडिंग साइट के रास्ते पर नाका लगाकर इसमें पैराग्लाइडिंग उड़ान का पूरा ब्यौरा दर्ज करना सुनिश्चित करें। समय-समय पर इस रिकॉर्ड का निरीक्षण कमेटी द्वारा किया जाए। इस दौरान एसडीएम विकास शुक्ला, संयुक्त निदेशक अभिमास रमन घरसंगी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुनयना शर्मा, डीएफओ एंजल चौहान, सदस्य रोशन लाल, विनय ठाकुर आदि मौजूद रहे।

गरीब बच्चों और असहाय लोगों का सहारा बनी मोनिका

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। जिला मुख्यालय की मोनिका सिंह गरीब बच्चों और असहाय लोगों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी हैं। जिले में कहीं भी गरीब बच्चों और असहाय लोगों की सूचना पाकर वह मौके पर पहुंच जाती हैं। वास्तु स्थिति और सारी चीजें जानने के बाद वह मदद करती हैं। उनका जज्बा है कि दो सालों में उन्होंने करीब 1,500 विद्यार्थियों की फीस भरकर उन्हें शिक्षित किया है। इनमें बीएड, बीसीए समेत अन्य कई कोर्स करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।

मोनिका सिंह अद्वैता फाउंडेशन के जरिये शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। विद्यार्थियों और महिलाओं को कानूनी जानकारियां देने के लिए भी शिविर लगवाकर उन्हें जागरूक कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को पठन सामग्री और अन्य सामान देकर सहायता कर रही हैं। जबकि घर में लाचार पड़े मरीजों के उपचार में भी मोनिका सिंह जरूरत के अनुसार आर्थिक सहायता देकर मदद कर रही हैं। पर्यावरण क्षेत्र में अद्वैता फाउंडेशन के माध्यम से हर साल 1,500 पौधे लगाने का लक्ष्य मोनिका ने रखा है। वह खुद पौधरोपण करने के अलावा अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। हर साल अभियान चलाकर लोगों को निशुल्क पौधे बांटने के अलावा उन्हें पौधे रोपित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मोनिका का लक्ष्य है कि इस साल एक गरीब बच्चे को डॉक्टर बनाना है। नीट पास कर चुके बीपीएल परिवार के एक बच्चे की फीस उनकी तरफ से भरी जाएगी इसमें पहली प्राथमिकता अनाथ बच्चे, बिना पिता के गरीब बच्चे की रहेगी।

सीएम सुक्खू ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली में मुलाकात की। सीएम मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री से पहली शिष्टाचार भेंट होगी। मुख्यमंत्री एक बार पहले भी नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट करने गए थे।

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद वह दिल्ली पहुंचे थे, मगर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उनका प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम टल गया। अब स्वस्थ होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें दोबारा से समय मिला है। सुक्खू 24 जनवरी को दिल्ली से हमीरपुर लौटेंगे। इसके बाद वह 25 जनवरी को वहां पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ही शिमला आएंगे।

रविवार को दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने द्वारका में हिमाचल सरकार की जमीन का मुआयना किया। उन्होंने यहां पर आर्थिक संसाधनों को विकसित करने के लिए विभिन्न संभावित प्रोजेक्टों पर चर्चा की। सुक्खू ने इस दौरान अधिकारियों को देशभर में हिमाचल सरकार की संपत्तियों का ब्योरा देने और उनका प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल सदन में कई गणमान्य लोगों से भी मिले। इनमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कई नेता और दिल्ली स्थित कई प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

नए मंत्रियों की नियुक्तियों पर चर्चा कर सकते हैं सुक्खू

सीएम सुक्खू आगामी दिनों में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में भी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं। वह कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से भी मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्रियों के अभी तीन पद खाली चल रहे हैं। इनके अलावा सुक्खू हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियों के बारे में भी हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं और दिल्ली से लौटने के बाद वे सरकार में इन पर फैसले ले सकते हैं।

कुलाला और शौल गांव में 17 दिन से बिजली नहीं

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

चम्बा। चुराह उपमंडल की बौंदेड़ी पंचायत के कुलाला और शौल गांव को 17 दिन बाद भी विद्युत बोर्ड बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं कर पाया है। बिजली आपूर्ति बंद होने का खामियाजा क्षेत्र के 150 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं, स्कूली बच्चों को 11 मार्च आरंभ हो रही दसवीं और जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी मोमबत्ती की लौ में करनी पड़ रही है। बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों को अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांवों का रुख करना पड़ रहा है।

वहीं, क्षेत्र में आटा चक्कियां भी बंद पड़ी हैं। ग्रामीणों को गेहूं पिसवाने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई को बहाल करवाने की मांग उठाई है।

कुलाला और शौल गांवों के लिए रखवाया गया ट्रांसफार्मर 17 दिन पूर्व जल जाने के बाद भी गांव आज तक रोशन नहीं हो पाए हैं।

बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने से ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे हैं। इतने दिन बाद भी बिजली सप्लाई सुचारू न होने से ग्रामीणों की जिंदगी आदिवासियों सी हो चुकी है।

ग्रामीण राकेश कुमार,लालचंद, हेमराज, किशन चंद, पिंकू, आलम राम, मानसा राम, जगदीश ने बताया कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद होने से लोगों विशेषकर गृहणियों और बीमार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि बिजली बिलों की समयानुसार अदायगी न होने पर बोर्ड प्रबंधन बिजली कनेक्शन काटने के लिए आदेश जारी कर देता है।

बिजली का ट्रांसफार्मर जलने से यह नौबत पेश आई है। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करवाने के लिए आलाधिकारियों को सूचित किया गया है। जल्द ट्रांसफार्मर की मरम्मत करवा दी जाएगी।

– दीवान चंद, सहायक अभियंता, विद्युत बोर्ड

सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटते ही हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ली है। जल्दी ही कई डीसी और एसपी के तबादले हो सकते हैं। कई विभागाध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर रात तक राज्य सचिवालय में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की है। चर्चा के बाद जिला शिमला और कुल्लूके पुलिस अधीक्षकों का तबादला हो गया है। अब अन्य जिलों पर भी विचार-विमर्श हो रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर रखे गए कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री से नजदीकी बनाए हुए हैं। कई अधिकारी डीसी और एसपी के रूप में अपनी नियुक्तियां चाह रहे हैं या फिर महत्वपूर्ण विभागों के निदेशक, निगमो-बोर्डों के प्रबंध निदेशक या अन्य पदों पर नियुक्त होना चाह रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी तो मंत्रियों और विधायकों से भी अपनी पैरवी करवा रहे हैं। ऐसे अधिकारी जयराम सरकार में अपनी अनदेखी का तर्क दे रहे हैं। कई अधिकारी तो खुद को सरकार के विचार से जुड़ा होने तक की भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय इस संबंध में गंभीरता से मंत्रणा कर रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नई दिल्ली से लौटते ही इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की एक और बैठक लेंगे। उसमें वह डीसी और एसपी की नियुक्तियों और तबादलों पर फैसला ले सकते हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री सुक्खू अधिकारियों के एकदम तबादले करने के ट्रेंड को न अपनाने की बात कर चुके हैं।

(चित्रकथा)

आज़ादी

गोपाल - अजय, यह लो तुम्हारा उपहार, तुम्हारा तोता। मैं तुम्हें समझा-समझा कर थक गया हूँ कि पक्षी खुले आकाश में खुश रहते हैं पिंजरों में नहीं । तुम्हारी

ज़िद के कारण मुझे लाना पड़ा । अजय - यह कितना प्यारा है! हम सब इसे 'मिट्ठू 'बुलाएँगे । गोपाल- तुम्हें पता है जब मिट्ठू खुश होता है तो 'राम-राम' भी बोलता है ।

अजय- पिताजी आप चिंता न करें । मैं मिट्ठू के खाने-पीने से लेकर उसके पिंजरे की साफ़-सफाई का पूरा ध्यान रखूँगा। अजय पूरे जी-जान से मिट्ठू का ध्यान रखने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर मिट्ठू ने कभी राम-राम नहीं बोला मानों उसका मन पिंजरे में न लगता हो। एक दिन

एक हफ्ता बिस्तर से उठ न पाया। वह खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगा था ।

गोपाल- क्या बात है बेटा , क्या सोच रहे हो?

अजय-पिता जी, मेरी समझ में आ गया है कि आज तक मिट्ठू ने घर पर कभी राम राम क्यों नहीं बोला । अब मुझे पता है कि कैद (बंधन) में सिर्फ घुटन होती है।

पता नहीं ,उसके मन में क्या आया और देखते ही देखते अजय ने बालकनी में जा कर पिंजरा खोल दिया । मिट्ठू फुर्र से बाहर निकल कर सामने की तार पर बैठ गया और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगा-राम राम ! राम राम !

-डॉ.कंचन शर्मा

हमारा संविधान

चलता जिससे देश है सारा वह है संविधान
भारत के नागरिक को प्यारा वह है संविधान
सबको एक बराबर जाने
बना कमजोर का सहारा वह है संविधान
बाबा अम्बेडकर ने अपनी कलम से स्वयं उतारा वह है संविधान
जुल्मी जालिम अत्याचारी के लिए
लगता है कारा वह है संविधान
आरक्षण का प्रावधान सुंदर करके
बना आँखो का तारा वह है संविधान
न्याय लोकतंत्र का सजग प्रहरी
डूबते का किनारा हो वह है संविधान
395 धाराओं में बंटा भारतवासी
की प्राण धारा, वह है संविधान।

लेखक-जय प्रकाश

बांस के उत्पाद तैयार कर जीवन में आई आर्थिक हरियाली, डलाह पंचायत की महिलाएं बनी आत्मनिर्भरता की प्रेरक

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

मंडी। सरकार से मिली मदद और अपने कौशल के संगम से मंडी जिला की डलाह पंचायत की महिलाएं उद्यमिता की ऐसी सफल गाथाएं लिख रहीं हैं, जो दूसरों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण भी बनी हैं। हरा सोना कहे जाने वाले बांस से विभिन्न उत्पाद तैयार कर महिलाओं ने अपने जीवन में आर्थिक हरियाली का नया मार्ग खोजा है। वहीं सेपू बड़ीए टेडी बीयरए स्वेटर जुराबें अगरबती इत्यादि तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर अपनी तकदीर को ही नहीं संवारा है, बल्कि अपने घर का सहारा भी बनी हैं।

जिला मण्डी के विकास खंड द्रंग की ग्राम पंचायत डलाह की महिलाएं आज स्वाबलंबन की मिसाल बनी हैं। कोठी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक खेती से हटकर अब बांस से उत्पाद तैयार कर रही हैंए महिलाओं का यह समूह बांस के उत्पाद बनाकर उन्हें बेचकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहा है। ये महिलाएं बांस की टोकरियां, किल्टे एसूप सहित बांस के उत्पाद बनाकर तीन से चार लाख रूपये तक आमदनी अर्जित कर रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बाहरी राज्यों में आयोजित मेलों में भी विक्रय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।

इन महिलाओं को मुख्यमंत्री ग्राम कौशल विकास योजना के तहत बांस उत्पाद बनाने का तीन महीने की ट्रेनिंग भी विभाग द्वारा दी गए है। ट्रेनिंग के दौरान इन महिलाओं को तीन हजार रुपए का भत्ता भी प्रतिमाह दिया गया। जिला मण्डी के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हिम ईरा नाम से मार्केट यार्ड खोला गया है जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है।

बांस के उत्पादों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं आमला, आम, नींबू, लिंगड के अचार के साथ सेपू बड़ी, अरबी डंठल बड़ी, माह बड़ी, अमचूर, ढींगरी मशरूमए हल्दी, खजूर व बांस के उत्पाद, कॉटन कुशन, टैडी बीयर, स्वैटर, जुराबें व ऊन के उत्पादों भी तैयार कर रहीं है। साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए गई अगरबत्ती, दीए, धूपबत्ती, मूर्तियों के साथ ही कई तरह के उत्पादों भी तैयार कर रहे हैं। लक्की कोठी स्वयं सहायता समूह की प्रधान कुसमा देवी का कहना है कि बांस के उत्पाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद तथा प्रशिक्षण दिया गया इसके साथ ही विपणन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी लेकिन अब बांस के उत्पाद तथा सेपू बड़ीए स्वेटरए अगरबतीए टेडी बीयर इत्यादि निर्मित कर अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं।

लकी कोठी समूह की सचिव अंजली कुमारी का कहना है कि उनके उत्पादों की डिमांड काफी रहती है मंडी शिवरात्रि तथा अन्य जगहों पर आयोजित मेलों में भी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की डिमांड काफी रहती है जबकि बांस से तैयार उत्पादों को अन्य राज्यों के मेलों में भी विक्रय किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई उनके हुनर की तारीफकरता है तो सुकूं मिलता है इसके साथ साथ ही आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भाव भी निर्मित होता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को स्टार्ट अप के लिए 2500 रू तथा रिवाल्विंग फंड के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 25000 रू की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रत्येक समूह को 50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला मण्डी के 14 ब्लॉक में कुल 7878 स्वयं सहायता समूहों में 60301 महिलाएं पंजीकृत हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार इन समूहों पर इस वर्ष मंडी जिला में 28 करोड़ खर्च कर रही है। ये सभी समूह बैंक से लिंक किए गए हैं।

मोहनलाल ब्राक्टा ने किया कुटाढा में पशु चिकित्सालय भवन का उदघाटन

कुटाढा पधारने पर क्षेत्र के लोगों ने पारंपरिक तरीके से किया स्वागत व अभिनंदन

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा ने रोहड़ू उपमंडल की पंचायत कारालश के बलसा में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के दो मंजिला भवन तथा कुटाढा में पशु चिकित्सालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलसा के निर्माण में 51 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ.साथ स्थानीय छात्र-छात्राओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने आने वाले बजट के अंतर्गत प्रधानाचार्य द्वारा नए भवन की मांग की पूर्ति का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कुटाढा में लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं के प्रति सकारात्मक सहयोग अपनाते हुए उसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया। स्थानीय प्रधान सुरेंद्र चौहान द्वारा पंचायत के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं को मुख्य संसदीय सचिव के सम्मुख रखा गया। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इसे जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव का अपने गृह क्षेत्र कुटाढा मैं पधारने पर क्षेत्र के लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष शिमला सुरेंद्र रेटका, मंडल अध्यक्ष करतार सिंह कुल्ला, उपाध्यक्ष कांग्रेस मंडल रोहड़ू बलदेव, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग आर एस जसवाल एसहायक निदेशक परियोजना पशुपालन विभाग रिनू सलारिया, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग यशपाल एअधिशासी अभियंता विद्युत संजीव रावत, उद्यान विभाग के डॉ संजय कुमार, विषय विशेषज्ञ कुशाल सिंह मेहता तहसीलदार रोहड़ू वरुण गुलाटी एवं कांग्रेस के पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। प्रधानाचार्य राकेश मुलटा ने स्कूल में विभिन्न समस्याओं के प्रति अवगत करवाया तथा मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

'आदर्श हिमाचल' अखबार के लिए मालिक, प्रकाशक व मुद्रक देविंद्र सिंह द्वारा सेट नं. 6, अप्पर कैथू, शिमला-3 से प्रकाशित और विज्ञापना इंटरप्राइजिज, दुर्गा काटेज, एसडीए काम्पलैक्स कुसुम्पटी से मुद्रित। आदर्श हिमाचल से संबंधित सभी मामलों का निपटारा न्यायाकि क्षेत्र शिमला में होगा। फोन नंबर-9857537874, 9418694594, 8091152022।